भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2118

दिनांकः 9 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

खिलौना निर्यात में कमी

2118 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खिलौना निर्यात के वर्ष 2021–22 में 177 मिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2023–24 में घटकर 152 मिलियन अमरीकी डॉलर रह जाने के क्या कारण हैं;

(ख) खिलौना आयात के वर्ष 2021–22 में 17 मिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2023–24 में बढ़कर 62 मिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) खिलौना अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) भारतीय खिलौना उद्योग को खिलौना विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी देश चीन से क्या सबक सीखना है; और

(ड.) क्या देश में खिलौना केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

***

(क) और (ख): – भारत के खिलौनों (एचएस 9503) के निर्यात में खिलौनों (एचएस 9503) की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण वर्ष 2021–22 में 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2023–24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की गिरावट आई है। यह देखा गया है कि यूएसए, यूके और जर्मनी सहित भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में भी खिलौनों के आयात में 16–20% की गिरावट दर्ज की गई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

देश	आयात मूल्य (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)		
	2021-22	2023-24	गिरावट %
विश्व	58.8	49.5	-16%
यूएसए	21.5	17.2	-20%
यूके	3.1	2.6	-16%
जर्मनी	4.2	3.5	- 16%

स्रोतः ट्रेडमैप (https://www.trademap.org)

सरकार की विभिन्न पहलों और घरेलू विनिर्माताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय खिलौना उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में खिलौनों का आयात वित्तीय वर्ष 2014–15 में 276 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 76% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी अवधि में खिलौनों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2014–15 में 41 मिलियन अमेरिकी

डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 271% की वृद्धि दर्ज की गई है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2023–24	वृद्धि/गिरावट%
आयात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	276	65	-76%
निर्यात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	41	152	+271%

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (https://commerce.gov.in)

हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय प्रतिकूलताओं, भू–राजनीतिक तनाव, लाल सागर संकट और खिलौनों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण, वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्यात में मामूली गिरावट आई है, जो 153.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 152.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। खिलौनों का आयात, जो मुख्य रूप से घरेलू उद्योग को सहायता देने वाला संघटक है, यह वित्तीय वर्ष 2022–23 में 62.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा सा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 64.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है।

(ग) से (ड.) – सरकार ने भारतीय खिलौना उद्योग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

- खिलौनों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें 21 विशिष्ट कार्य बिंदु शामिल हैं और इसे 14 मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा 25.02.2020 को खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से 01.01.2021 से खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है।
- खिलौनों (एचएस कोड 9503) पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) फरवरी 2020 में 20% सें बढ़ाकर 60% कर दिया गया है और बाद में 2023 में इसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।
- जुलाई 2024 तक, बीआइएस ने खिलौना उद्योग की सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप खिलौनों पर बीआइएस मानक चिह्न के उपयोग के लिए घरेलू खिलौना निर्माताओं को 1509 लाइसेंस और एक विदेशी निर्माता को 38 लाइसेंस प्रदान किए हैं।
- एमएसएमई मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि स्कीम (एसएफयूआरटीआइ) के अंतर्गत 19 खिलौना समूहों को सहायता प्रदान कर रहा है, तथा वस्त्र मंत्रालय 26 खिलौना समूहों को डिजाइनिंग और टूलिंग सहायता प्रदान कर रहा है।
- स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 250 खिलौना स्टार्टअप की पहचान की गई है जिसके तहत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत भारत से खिलौनों के निर्यात के लिए शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की गई है जिनमें शामिल हैं, भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत–यूएई सीईपीए), भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत–ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए), भारत–यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत–ईएफटीए ईपीए)।
- स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने और नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई संवर्धनात्मक पहल भी शुरू की गई हैं, जिनमें टॉयकाथॉन, स्थानीय खिलौना मेले, स्वच्छ टॉयकाथॉन, खिलौना व्यापार एक्सपो को सहायता आदि शामिल हैं।
- अवसरों की पहचान के लिए ई–कॉमर्स इकाइयों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

*****